के बजट में व्यवस्था के सम्बन्ध में 28 मार्च 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4976 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाली जिले को पिछड़ा हुआ जिला घोषित न करने के क्या कारण है जबकि जोधपुर, जालौर, सिरोही तथा अन्य जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : रियायती दर पर धनराशि प्राप्त करने के हकदार, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए अपनाये जाने वाले मार्गदर्शी मापदण्ड सभी राज्यो को बात दिये गये है । इन मापदण्डो के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ो के संदर्भ में राजस्थान राज्य सरकार ने पाली जिले का रियायती दर पर धनराशि पाने योग्य नही ठहराया है ।

Utilisation of Eucalyptus Forest for Newsprint in West Bengal

449. SHRI S. C. BESRA:
SHRI S. N. SINGH DEO:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state.

(a) whether eucalyptus forest raised for the newsprint industry is ready in the West Bengal for harvesting,

(b) whether the newsprint factory for which it was grown is yet to be decided; and

(c) if so, how Government propose to utilise the newly raised forest?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): (a) Yes Sir, but it is for Paper Mills and not for Newsprint

(b) Does not arise.

(c) To be utilised by paper mills of West Bengal.

"सिटीज आफ टुमारो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

450. श्री मूल चन्द डागा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मई, 1973 के "दी हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सिटीज आफ टुमारो" शीर्षक से प्रकाशित सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हा, तो नगरों की स्थिति मे सुधार करने सम्बन्धी योजना की मुख्य बाते क्या है और उसमें नगरीय इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और नगर पालिकाओ का योगदान और कृत्य क्या होगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) दिनाक 28 मई, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित सम्पादकीय "सिटीज आफ टूमारो" पांचवी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को योजना आयोग द्वारा भेजे गये मार्गदर्शी सिद्धांतों पर टिप्पणी करता है और प्रत्येक शहर में उसकी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जाने वाली दीर्घकालीन वृहद योजनाओं की आवश्यकता की ओर इंगित करता है । यह इस पर भी बल देता है कि शहरी क्षेत्र में प्राधिकरणों की बहुलता से बचने की आवश्यकता है ।

आयोग द्वारा जो मार्गदर्शी सिद्धांत जारी